सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यकरण

2421. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण में कोई सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार लाने और इन केन्द्रों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति हेतु सहायता करने के लिए क्या प्रयास किए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन केन्द्रों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति एवं इनका कार्यकरण असन्तोषजनक रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिरुवेरा): (क) राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण किया जाता है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह दी जाती है कि वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पड़े हुए सभी पदों को भर दें और इन केन्द्रों में दवाओं का पर्याप्त रूप से प्रबन्ध करें। इन केन्द्रों के अर्धचिकित्सीय तथा चिकित्सीय कार्यकर्ताओं की क्षमता और प्रभावकारिता सुधारने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तेज किये गये हैं।

Allotment of shares to PSU employees

2422. SHRI V. HANUMANTHA RAO:
SHRI SANJAY DALMIA:
DR. BAPU KALDATE:
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have decided to allot shares to the employees of public sector undertakings; and

(b) if so, the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) The Government has decided to offer shares to the employees of those public enterprises in which Government has disinvested its equity shareholdings. Employees of 21 public enpterprises have already been offered shares.

Sanctions of Renewable Energy Projects by Ireda to Bihar

2423. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State of Bihar has been sanctioned only four Renewable Energy Projects by the Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) since 1987-88 to date whereas *Karnataka, Maharashtra and Tamil* Nadu were sanctioned 50,67 and 132 projects during the said period;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps Government propose to take to remove the injustice being perpetuated against Bihar by IREDA in respect of renewable energy projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes.

(b) IREDA sanctions technically and financially viable projects to entrepreneurs/developers. These projects may be from any State. States like Tamil Nadu, Maharashtra and Karnataka have adopted progressive policies for promoting New and Renewable Sources of Energy. Thus, a large number of technically and financially viable projects were received from these States and were sanctioned by IREDA.